आकाशवाणी गोरखपुर
प्रादेशिक समाचार

दिनांक–**02 सितंबर** 2026 **7:20 AM**

पहले मुख्य समाचार।

- प्रदेश भर में सत्रह सितंबर से सत्रह अक्टूबर तक चलाया जाएगा सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर इस अभियान को जनभागीदारी से व्यापक बनाने के दिए निर्देश।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एमएसएमई अवार्ड समारोह में लिया हिस्सा। कहा– विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है एमएसएमई सेक्टर।
- सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का दिया आदेश।
- रुक–रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के उन्नीस जिले बाढ़ से प्रभावित। राहत और बचाव कार्य जारी।

****

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 'सेवा संकल्प अभियान' की कार्ययोजना को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। यह अभियान प्रदेश भर में सत्रह सितंबर से सत्रह अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचीस वर्षों के निरंतर सेवा काल की जनकल्याणकारी उपलब्धियों को जन–जन तक पहुंचाना है। इसके जरिए प्रत्येक नागरिक को 'विकसित भारत दो हजार सैंतालीस' के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ने की कोशिश होगी।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 'सेवा संकल्प अभियान' को जनभागीदारी का व्यापक अभियान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान के प्रभावी संचालन के लिए शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय और जनपद स्तर पर समन्वय की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए।

****

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से आयोजित एमएसएमई अवार्ड समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि एमएसएमई विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है।

विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कोई सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि एमएसएमई की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक रूप से मजबूत भारत ही नहीं होता है बल्कि ऐसा भारत है जो मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबली कॉम्पिटेटिव हो। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अग्रणी हो, युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करें और अपनी स्ट्रेटेजिक तथा इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज में भी वह आत्मनिर्भर हो।

****

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में 'प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना' की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया।

योजना के छह लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22 दशमलच पांच–चार से बढ़कर जुलाई 2026 में 38 दशमलव आठ–पांच हो गया, जो 16 दशमलव तीन–एक अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ–साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजनाओं में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ, नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।

****

रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष सात सौ बारह किलोमीटर रेलमार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए एक सौ सत्तर करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच परिचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एक ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है।

****

सर्वोच्च न्यायालय ने बीस से पचीस जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुडी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केन्द्र सरकार सहित पांच राज्यों की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर–मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले दो हजार आठ सौ तिहत्तर लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। इस बीच, केंद्र सरकार ने कॉक्रोच जनता पार्टी–सीजेपी के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।

हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किये गये मामले वापस लिये जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में, जो सरकारें थी, उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस–कॉन्फ्रेस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, हम उस का स्वागत करते हैं।

****

चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा चार हजार क्विंटल से घटाकर दो हजार क्विंटल कर दी है। साथ ही देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है।

चीनी के भंडारण की नई सीमा इस महीने की 15 तारीख से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, संशोधित नियमों के तहत कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। सरकार ने भरोसा दिया है कि इस फैसले से बाजार में चीनी की कमी नहीं होगी और कीमतें काबू में रहेंगी। उधर, प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए नासिक से भेजी गई पहली कांदा एक्सप्रेस 450 मीट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है, जिसे दिल्ली–एनसीआर, वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़ और अमृतसर में वितरित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाजार में प्याज आते ही कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में दाम और कम होंगे। रेलमार्ग से प्याज की सुरक्षित आपूर्ति के लिए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समाचार कक्ष से शैलेन्द्र शर्मा।

****

हरियाणा के पलवल जिले में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में मैनपुरी के लोगों की मृत्यु का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। पलवल में केएमपी एक्सप्रेस–वे पर कल सुबह एक पिकअप सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। इस दुर्घटना में पिकअप में सवार छह लोगों की मौत हो गयी जबकि सोलह लोग घायल हो गये। यह लोग राजस्थान के खाटू श्याम बालाजी दर्शन के बाद मथुरा के वृन्दावन आ रहे थे।

****

रुक–रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के उन्नीस जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट–

प्रदेश में बारिश से होने वाली जनहानि, पशु हानि और आर्थिक हानि को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड पर निकलने के दिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वर्षा, आकाशीय बिजली से हुए नुक्सान का आंकलन कर, दो से चार घंटे में मुआवजा देने का निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित परिवारों तक भोजन, राहत सामग्री और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 549 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और 248 मेडिकल टीमें तैनात हैं। इसके अलावा लोगों को सुरक्षित निकालने और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के लिए 552 नाव एवं मोटरबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावितों के लिए 312 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इन राहत शिविरों में करीब 1700 लोग रह रहे हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।

इस बीच, मौसम विभाग ने दो दिनों में प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

****